Setting up of building centres in districts by HUDCO

♦251. SHRI VIRENDRA VERMA: SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether HUDCO proposes to set up building centres in all the districts in the country;

(b) if so, whether such districts have been identified and if so, what are the details thereof; and

(c) what are the precise functions of these centres and by when these centres are likely to come up?

THE MINISTER[1] OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

With view to providing easy access to low cost housing materials and techniques, Government has decided to set Up a national network of Building Centres. The Housing & Urban Development Corporation has been entrusted with the overall responsibility of implementation of this programme and monitoring its progress.

While its is proposed to ultimately set up at least one Building Centre in each District, setting up of 100 such Centres has been envisaged during the current year. The State Governments/Union Territory Administrations have been requested to identify the districts/locations where the Centres may be set up and forward their requisite proposals to HUDCO.

The main functions of the Building Centres are the following:—

(i) encouraging the production and use of low cost buildTng materials and components based on local resources,, agricultural and industrial wastes, recycled materials etc.;

(ii) imparting training to local artisans and unemployed youth in low cost building technologies and promoting the upgradation of traditional construction practices and technologies;

(iii)' stocking and selling of various low cost building materials and components; and

(iv) promoting low cost house designs suitable to the life style of the local people.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने बताया है कि कम लागत के भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों को सुगमता से उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने भवन केन्द्रों का एक राष्ट्रीय नेट वर्क स्थापित करने का निर्णय किया है तो मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि कब से और कहां कहां पर इस प्रकर के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं ।

मान्यवर, क्योंकि इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि करन्ट ईयर में 100 इस प्रकार के जिलों में केन्द्र स्थापित करेंगे तो माननीया मंत्री महोदया यह बतायें कि इस साल में 100 खोलेंगे तो अब तक कितने जिलों में इस प्रकार के नेटवर्क स्थापित किये जा चुके हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह जो लो कास्ट बिल्डिंग मैटीरियल सेन्टर खोलने की बात थी यह अभी 88 का बजट जो वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने यह घोषणा की थी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर ही ऐसा खोलेंगे और इस साल में 100 सेन्टर खोलेंगे, जैसा कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी कह रहे हैं । स्टेट और

[1]The question was actually asked on the floor of the House by shri Virendra Verma.

सेन्ट्रल गवर्नमेंट दोनों इसको खोलेंगे । स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने लिखा है, यूनियन टैरटरी को भी लिखा है कि वह हमें लोकेशन बतायें कि किस जिले में कहां वह सेन्टर खोलना चाहते हैं । जब उनके यहां से जवाब आ जाएगा तो देखेंगे । अभी तक 42 जगहों से आया है, महाराष्ट्र, यू.पी. बिहार, बंगाल, हर जगह से आ रहे हैं। लेकिन अभी तक मामला अंडर कंसीडरेशन है । पूरी तरह से यह तय नहीं किया गया है कि कहां-कहां पर खोलने हैं । जैसे ही यह तय होगा कौन से जिलों में स्टेट गवर्नमेंट्स चाहती है तो वहां खोल दिए जायेंगे । इस वक्त एक सेन्टर चल रहा है निज्जामुद्दीन, दिल्ली में और एक केरल में कोवलम में चल रहा है जो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं । सबसे बड़ा मकसद यह है कि इस समय हाउसिंग स्टाक बढ़ाना है उसके लिए जरूरत इस बात की है कि लो कास्ट बिल्डिंग मैटीरियल का हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और उस को काम में लावें । जो इंडस्ट्रीयल वेस्ट हैं . . .

श्री सभापति : इस साल में आप 100 खोलेंगे ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : सौ खोलने की योजना है । 88 के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी और 89, मार्च तक खत्म करेंगे । लेकिन हम आपको यह बतायेंगे कि आम पेपर यह पूरा नहीं कर सके हैं । 100 हम खोलेंगे । जहां इसकी यूटिलिटी है वहां खोलेंगे । इन सेन्टर्स का सबसे बड़ा मकसद यह है कि लो कास्ट बिल्डिंग मैटीरियल की तरफ लोगों को हम लाये। जिस रीजन में जिस जगह जो सूटबल मैटीरियल हो उसकी तरफ ध्यान दें, उसकी रिसर्च करायें। जो वहां के अन-एम्प्लायड यूथ है उनको ट्रेनिंग दें । जैसे हर गांव में आर्टीजन होते हैं, मजदूर होते हैं और दूसरे लोग होते हैं उन सबको वहां ट्रेनिंग दें । यह नेट वर्क शुरू करें जिसके जरिये एम्प्लाईमेंट मिले और छोटी-छोटी इंडस्ट्री लगा सकें ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करें कि क्या उन्होंने अभी तक देश में किसी भी स्थान पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की है ? यदि की है तो कहां-कहां और कितने आदमियों को अभी तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है ? दूसरा पार्ट मेरा कम लागत, विभिन्न निर्माण सामग्री और घटकों के भंडारण और बिक्री के बारे में है । मंत्री महोदया यह बतायें कि जो इस प्रकार का कम लागत का सामान वह बनवा रहीं है, क्योंकि हिन्दुस्तान गरीब देश है, गरीब ज्यादातर गांव में रहते हैं, शहरों में भी हैं, तो उनके लिए क्या उन्होंने कहां इस प्रकार के सामान का निर्माण कराया है, भंडारण कराया है । यदि हां, तो कहां-कहां ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : ट्रेनिंग की बात पहले ले रही हूं । इसमें अभी तक हम शिविर लगाते थे और ट्रेनिंग उनको देते थे । 15 दिन की, एक हफ्ते की, दो हफ्ते की । यहां दिल्ली में हुई उसमें बहुत सी हमारी बहनें, भाई शामिल हुये । हमने सबको सर्टीफिकेट वगैरह बांटे । इन सेन्टर्स का खोलने का मतलब यह है कि लो कास्ट टक्नोलोजी के द्वारा काम किया जा सके । मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो केरल में कोवलम में सेन्टर खोला है वह बहुत अच्छा काम कर रहा है । वहां मड हाउसेज बनाने की योजना है । मड के बहुत खूबसूरत हाउसेज बन रहे हैं ।

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Kerala is very effective in every field.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: It is working for the last two or three years. It is not your Government's achievement.

तो मैं यह बात कह रही थी कि जैसे हम लोग देहातों में मिट्टी काम में लेते हैं उसी प्रकार से मिट्टी में चूना मिला दें, थोड़ासा सीमेंट मिला दें और छोटी-छोटी मशीनों से जो 15 से 35 हजार तक की होती हैं उनसे प्रेस किया जाता है । इसकी लाइफ 50 साल तक की है । उसी प्रकार से थैचज होते हैं, छप्पर डालते हैं, उनमें कुछ इस प्रकार का केमिकल डालकर उनको वाटर प्रूफ बनाने की कोशिश की जाती है । ये सब कोशिशें की जा रही हैं ।

हमारा मकसद है कि इन सेन्टर्स की व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो ।

श्री सभापति : आप इनको जल्दी से जल्दी कर दीजिए ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : जी हां, हम इनको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: श्रीमन्, मेरे प्रश्न के का उत्तर नहीं आया है । मैंने पूछा है जो मैटीरियल आप बता रहे हैं, क्या उसके भंडारण की भी आपने व्यवस्था की है ? मैं सप्लाई के बारे में नहीं पूछ रहा हूं ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं चाहूंगी कि हमारे माननीय सदस्य हमने जो निजामुद्दीन में सेन्टर बनाया है वहां चलें और देखें कि हम इस बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वर्मा जी, वे कह रही हैं कि आपको ले जायेंगे ।

श्रीमती मोहसिना किदवई: वाजपेयी जी, आपको भी ले जायेंगे।

श्री ईश दत्त यादव : माननीय सभापति जी, माननीया मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है वह सन्तोषजनक नहीं है . . . **(व्यवधान)** ।

SHRI A. G. KULKARNI; Sir, once and for all, this designation must be " fixed. Last time also we discussed this and you said "Mantri Mahodaya" is all right. Now he says "Mantarani". Kindly give a complete, SansKritised Hindi version, of what it should be.

SHRI ISH DUTT YADAV; No, no, I lid not call her "Mantarani".

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : आप तो पंडित हैं, कुछ बता दीजिए ।

SHRI N. E. BALARAM; "Mantararu" is the apt. word.

श्री सभापति : आप भी पंडित हैं, पंडितों की हाउस में कमी नहीं है, यहां सभी मौजूद हैं ।

श्री भजन लाल: इनसे पूछिए कि ये अपनी धर्मपत्नी को "मंत्री" कहते हैं या "मंत्राणी" कहते हैं ।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : अटल जी, आप तो शंकराचार्य हैं, कुछ बता दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : "मंत्री महोदया" ठीक है ।

श्री सभापति : उस दिन भी कहा गया था कि "मंत्री महोदया" सही है । उसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री ईश दत्त यादव : माननीय सभापति जी, मैंने "माननीय मंत्री महोदया" कहा है, "मंत्राणी" नहीं कहा है । "मंत्राणी" सही नहीं है। माननीय कुलकर्णी जी ने सही बात सुनी नहीं है । मैंने "मंत्री महोदया" ही कहा है और यही शुद्ध शब्द भी है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, क्या माननीया मंत्री महोदया उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही इस तरह का केन्द्र स्थापित करेंगी और क्या अभी तक उत्तर प्रदेश में इस तरह का केन्द्र स्थापित किया गया है या नहीं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, मैंने पहले ही कहा है कि स्टेट्स गवर्नमेंट्स को लिखा गया है और तकरीबन हर स्टेट का उत्तर आ चुका है । उनके प्रोपोजल्स अण्डर कंसीडरेशन हैं । कहां स्थापित होगा, यह स्टेट गवर्नमेंट के साथ

य करना होगा, यह ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की है । उनको लिखकर भेजा गया है और उसके बाद ही उनको स्थापित किया जाएगा । इसीलिए यह योजना बनाई गई है ताकि हमारी तरफ से कोई कमी न हो :

श्री सभापति : आप इसमें जल्दी कर दीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीया मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में बताया है कि जो साधारण व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लो कास्ट मैटीरियल उपलब्ध कराया जाएगा क्योंकि बराबर मकानों पर लगने वाले सामानों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लो कास्ट मकान हैं उनकी लागत क्या निकलती है ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, औसत लागत तो डिजाइन के ऊपर निर्भर करती है. जो मुझे बताया गया है, जो मकान पक्के ईंटों से बनाये जाते हैं उनमें लोहा, सीमेंट आदि ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन जो लो कास्ट टेक्नालाजी में कीमत में 15 से 20 परसेंट का फर्क पड़ता है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : लो कास्ट डिजायन का जो प्रोपोजल है कि इसकी लागत कितने रुपए आयेगी । मैं फर्क नहीं पूछ रहा हूं कि 15 प्रतिशत है या 20 प्रतिशत है ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, मैंने बताया है कि यह निश्चित नहीं है । यह इस चीज पर आधारित है कि कितने कमरे होंगे, कितना बड़ा मकान होगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मंत्री महोदया का उत्तर है कि "(iv)* promoting low cost house designs suitable to th* life[1] style of the local people".

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस हिसाब से कोई तो आंकड़ा निकाला होगा कि लो कास्ट डिजाइन के जो मकान होंगे उनकी लागत कितनी आयेगी ।

SHRI MURASOLI MARAN: What is the lowest, what is the highest?

श्रीमती मोहसिना किदवई : इट आल डिपेंड्स आफ दि साइज । कितना मैटीरियल इसमें लगना है, दो मंजिला बनानी है या एक मंजिला बनानी है इट आल डिपेंड्स आफ दि साइज । लेकिन मैटीरियल जो लगेगा उस हिसाब से पक्की ईंटों, लोहे और सीमेंट से जो मकान बनते हैं उनमें और इन लो कास्ट बिल्डिंग्स में 15–20 परसेंट का फर्क होता है । . . . . (व्यवधान) . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इसके मायने यह है . . .

श्री सभापति : हाउस में जवाब दे दिया है ।

It will depend on the size of the house, the type of the house you want to build—with a verandah or with 10' x 6' rooms, or with eight room or a two-room house with a kitchen and so on.

आप सब चीजें जानते हैं . . . (व्यवधान) . . .

लो कास्ट हाउस सभी होंगे लेकिन जिसकी फेमिली बड़ी है उसके बड़े कमरे होंगे ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, in her reply the honourable Minister has stated about one building centre for each district. Under that, about 100 district centres would be set up. I would like to know from the hon. Minister what is the total estimate of construction of those buildings for helping the economically weaker

sections. That is number one. Secondly, what is the mode of recovery of the money from the occupants by HUDCO?

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Sir, we are not going to construct houses for the weaker sections. That is another scheme of HUDCO and ther sre financing that—for weaker sections as well ag LIG. This is only for low cost building materials centres that we are going to set up.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : सभापति महोदय, आपने जो मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद। मंत्री महोदया ने इस प्रश्न के संबंध में कहा है कि राज्यों को लिखा गया है और कुछ राज्यों ने अपना जवाब भेज भी दिया है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्य के जिलों में इनको बनाने की सूचना दी है? दूसरा यह कि यह स्कीम तैयार होने के बाद देश के सिर्फ एक राज्य केरल में इसकी शुरूआत हुई है। बाकी किसी भी राज्य में इसकी शुरूआत नहीं हुई है। हमारा इतना बड़ा देश है और मैं समझता हूं कि इस रफ्तार से इसमें कई साल लग जायेंगे। क्योंकि मंत्री महोदया ने बताया कि अभी तक केवल केरल में शुरू हुआ है और किसी भी राज्य में इस पर अमल नहीं हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने जवाब दिया है और किन-किन राज्यों से जवाब आना है?

श्रीमती मोहसिना किदवई : जहां तक राज्यों का सवाल है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा और यूनियन टैरोटरीज, इन्होंने कहा है कि हम सेट-अप करना चाहते हैं। लेकिन अभी उन्होंने जिलों के बारे में लिखकर नहीं दिया है कि वे किस जिले या ब्लाक में करना चाहते हैं। जहां तक बिल्डिंग मैटीरियल का सवाल है मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान वह जगह है, आपको याद होगा कि जब यहां यूरिया खाद और पोटाश खाद आई तो वह लोगों को मुफ्त देते थे, किसानों को मुफ्त देते थे लेकिन तब भी किसान उसको अपने खेतों में नहीं डालते थे कि जमीन बंजर हो जायेगी। इसमें रूजूह करने का सवाल है कि लो टक्नोलाजी की तरफ. .

श्री सभापति : आप भी रुजूह करने की कोशिश कर रहीं हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वह जैसा कहेंगे हम करेंग।

श्री सभापति : हो गया आपका जवाब।

*2S2. (Transfarred to the 18th August, 1988)

Promotion of Indian Cultural Heritage on Doordarshan

*253. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Doordarshan proposes to prepare programme to promote Indian cultural heritage;

(b) whether there is any proposal to prepare programmes fa collaboration with various Zonal Cultural Centres; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF . STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Yes, Sir. Doordarshan is already doing so.

(b) and (c) No, Sir. However, programme prepared by Zonal Cultural Centres and the coverages made by Doordarshan of their festivals are telecast from Doordarshan,

MR. CHAIRMAN: Question Hour *is* over.